संवैधानिक सुधारो मे व्यापकता था फिर भी उसमे अनेक त्रुटियाँ थी। जैसे निरंकुश नरेशो को कौरतंत्रीय प्रशासन मे जीरा जाना। गवर्नर जनरल और प्रान्तिय गवर्नरो के विशेषाधिकारो ने वास्तव मे जनतंत्रीय एवं जिम्मेदार सरकार के अस्तित्व पर प्रश्न वाचक चिन्ह लगा दिया।

तात्कालीन प्रमुख राजनेताओं के द्वारा इस एक्ट के विषय मे की गई प्रतिकूल टिप्पणियो से भी उनके असंतोष साफ तौर पर झलकते हैं। पंडित नेहरू ने इसी दासता का नया चार्टर बताते हुए कहा कि "We are Provided with a car, all brakes and no engine"

जिन्ना ने उसे पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया, तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसे बाह्य रूप से कुछ जनतंत्रीय परन्तु अन्दर से पूर्णत: खोखला बताकर इस एक्ट की आलोचना की। सी० राजगोपालाचारी ने तो उसे दोहरी शासन से भी बुरा मानकर अपनी शुद्धता प्रदर्शित की।

वैसे भी यह अधिनियम नागरीक अधिकारो के बारे मे मौन रहा। फिर भी अनेक खामियो के बावजूद 1935 का एक्ट संवैधानिक सुधारो की श्रृंखला मे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे इंकार नही किया जा सकता है।

The end